ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 270-273
ISSN NO.-2347-2944
Vol.-10, No.-I, Issues-11 YEAR- June -2019

भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ विशेष में आर्थिक सुधारों पर एक दृष्टि

डॉ0 आशा साहू
एसोसिएट प्रोफेसर– अर्थशास्त्र विभाग, नेहरू पी. जी. कॉलेज, ललितपुर (उ0प्र0), भारत

Received- 07.05.2019, Revised- 12.05.2019, Accepted - 17.05.2019 E-mail: -profashasahu07@gmail.com

सारांश : ***बाजारोन्मुखी, प्रतिस्पर्धात्मक और उन्मुक्त अर्थ पद्धति के आधार पर सम्पूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को एक ही धारा में प्रवाहित करने का प्रयास दिनोदिन तेज होता जा रहा है और इस प्रयास में अमेरिका तथा उसके सहयोगी देशों और विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश तथा विश्व व्यापार संगठन जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को पर्याप्त सफलता मिल रही है, सभी देशों की अर्थव्यवस्था का संचालन सर्वानुमति से समान सिद्धांतों के आधार पर होना ही आर्थिक वैश्वीकरण है। सन् 1981 के बाद से पूरे विश्व में आर्थिक सुधारों का दौर प्रारम्भ हुआ, वह एल. पी. जी. के रूप में जाना जाता है।***

अस्सी के दशक से विश्व की आर्थिक स्थितियों में आए महत्वपूर्ण परिवर्तनों ने आर्थिक सिद्धांतों के नए पहलुओं पर विचार करने पर बाध्य कर दिया। स्वतंत्रता के बाद चार दशकों की संरक्षणात्मक नीति ने भरतीय उद्योगों को गुणत्मक रूप से कमजोर बनाया है। स्वतंत्रता के बाद से सरकारी नीतियों का उद्देश्य समता और सामाजिक न्याय सहित तीव्र विकास और संतुलित आर्थिक विकास रहा है। इसी कारण नई आर्थिक नीति को आवश्यक समझा गया। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों की श्रृंखला आरम्भ करके देश की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयास किए गए।

कुंजीभूत शब्द– नई आर्थिक नीति, भारतीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक सुधार, मुद्रा स्फीति, औद्योगिक नीति।

प्रस्तुत शोधपत्र में वर्णनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत शोधपत्र में द्वितीयक समंको प्रयोग किया गया है जो उपलब्ध सम्बद्ध प्रकाशित आलेखों, पुस्तकों से संकलित किए गये है। प्रस्तुत शोधपत्र के उद्देश्य निम्नलिखित है –

भारतीय अर्थव्यवस्था में नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत अपनाए गए आर्थिक सुधारों का अध्ययन करना।

नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत पाई जाने वाली कमियों का अध्ययन करना।

नई आर्थिक नीति– भारत में 1991 में डॉ. मनमोहन सिंह जी द्वारा आर्थिक सुधारों के रूप में एल. पी. जी. को अपनाया गया। नई आर्थिक नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की प्रक्रिया का सूत्रपात किया। उदारीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें देश के शासनतंत्र द्वारा अपनाए जा रहे लाइसेंस, नियंत्रण, कोटा, प्रशुल्क आदि प्रशासकीय अवरोधो को कम किया जाता है ताकि देश को आर्थिक विकास के मार्ग पर ले जाया जा सके। भारत की नई आर्थिक नीति में उदारीकरण की दिशा से जुड़ा एक अन्य पहलू है– निजीकरण लोकउपक्रमों की बढती अक्षमता और बढते घाटे को ध्यान में रखकर विगत वर्शो में सार्वजनिकीकरण की नीति के स्थान पर निजीकरण तथा अपनिवेश की नीति को बढावा दिया गया, इसके अतिरिक्त इस नीति में लोकउपक्रमों के कार्यक्षेत्र को कम करके निजी उद्योगो उदारवादी लाईसेंसिंग नीतियो के अन्तर्गत कार्य करने की विस्तृत सुविधाए प्रदान की गई।

वैश्वीकरण शब्द अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गुंजायमान है। यह शब्द व्यापार अवसरों की जीवन्तता एवं उनके विस्तार का घोतक है। वैश्वीकरण वस्तुतः क्रिया कलापों विशेशकर विपणन सम्बंधी क्रियाओं का अन्तर्राश्ट्रीयकरण करना है जिसमें सम्पूर्ण विश्व बाजार को एक ही क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। अर्थात् वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न हो जाती है और व्यापार देश की सीमाओं में न रहकर विश्व व्यापार में निहित तुलनात्मक लागत लाभ दशाओं का विदोहन करने की दिशा में अग्रसर होता है।

आर्थिक नीति का मौलिक उद्देश्य अर्थव्यवस्था को स्थिरता के साथ आर्थिक विकास के मार्ग पर आगे बढाना है। भारतीय आर्थिक नीति 1991 के अर्न्तगत निम्नांकित क्षेत्रों में नई रणनीति अपनाई गई–

औद्योगिक नीति में सुधार– देश के घरेलू उद्योगों को अन्तर्राश्ट्रीय प्रतिस्पर्धा योग्य बनाने के उद्देश्य से 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति की घोशणा की गई। इसी संदर्भ में 14 अप्रैल 1993 को सरकार ने लाइसेन्स की अनिवार्यता रखने वाले उद्योगों की संख्या 18 से घटाकर 15 कर दी गई वर्तमान में इनकी संख्या 2 है। एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रवृत्तियां अधिनियम को संशोधित किया गया और बिना पूर्व अनुमति के फर्मो को अपनी क्षमता का विस्तार एवं अपनी क्रियाओं का विविधीकरण करने की छूट दे दी गई। उत्पादकता में गुणात्मक सुधार के लिए विदेशी तकनीक के आयात प्रतिबंधों को उदार एवं मुक्त बनाया गया। इस प्रकार बहुआयामी औद्योगिक नीति सुधारों द्वारा भारतीय

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-10, No.-I, Issues-11 YEAR- June -2019

उद्योग में संरक्षणवाद को समाप्त करके प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का सूत्रपात किया गया।

आयात निर्यात नीति में सुधार– भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की सुधारात्मक नीतिगत श्रृंखला के अन्तर्गत सरकार ने 8वीं पंचवर्षीय योजना नई आयात नीति की घोशणा की, जिसका उद्देश्य व्यापार में न्यूनतम प्रतिबंध, अधिक स्वतंत्रता एवं न्यूनतम प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करना है। 1993 में पुनः संशोधन करके कृशि क्षेत्र की निर्यातोन्मुखी इकाइयों को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई गई।

राजकोशीय अनुशासन– केन्द्रीय सरकार ने वित्तीय अनुशासन लागू करने के प्रयास एवं राजकोशीय घाटे को नियंत्रित करने के नीतिगत उपाय आरम्भ किए। सकल राजकोशीय घाटा 1980–81 में 6.1 प्रतिशत था, जो 1990–91 में बढकर 8.4 प्रतिशत हो गया। जिसे 1991–92 घटाकर 5. 6 प्रतिशत कर दिया गया। 2001–02 में सकल राजकोशीय घाटा बढकर 6.2 प्रतिशत हो गया। 2017–18 में यह पुनः घटकर 3.5 प्रतिशत हो गया जो तालिका कमांक 1 से स्पष्ट है।

तालिका –1

भारतीय अर्थव्यवस्था में राजकोशीय संकेतक

प्रतिशत में

क्र	संकेतक	1991	2001	2011	2018
1	सकल राजकोशीय घाटा	5.6	6.2	5.1	3.5
2	राजस्व घाटा	3.3	4.1	3.4	2.8
3	प्राथमिक घाटा	1.5	0.5	2.0	0.4

स्त्रोत– आर्थिक समीक्षा 2008–09, 2018–19

विदेशी निवेश नीति में सुधार– इस नीति में सुधार के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेरा में संशोधन करके विदेशी निवेश सम्बंधी प्रतिबंधों को यथा–सम्भव समाप्त कर दिया गया। फेरा के स्थान पर फेमा लागू किया गया।

कर संरचना में सुधार– डॉ. राजा चैलैया की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकार ने वर्श 1993–94 के बजट प्रस्तावों में सीमा शुल्कों एवं उत्पाद शुल्कों में व्यापक कटौती की। सरकार ने प्रत्यक्ष करों में अनेक रियायतें प्रदान करके कर ढांचे को सरल बनाया।

अवमूल्यन नीति– निर्यात को प्रोत्साहित करने, विदेशी अदायगियों को सुदृढ बनाने और भारत से पूंजी पलायन को रोकने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 1991 में दो चरणों में भारतीय रूपये का अवमूल्यन कर रूपये की विनिमय दर में समायोजन किया। अवमूल्यन नीति का उद्देश्य निर्यात को बढाकर प्रतिकूल संतुलन की समस्या का समाधान ढूढना था।

रूपये की परिवर्तनीयता– विदेशी मुद्रा की काला बाजारी वाले हवाला बाजार की गैर कानूनी गतिविधियों को सीमित करने के लिए 1992–93 के बजट प्रस्तावों में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली आरम्भ की और रूपये को आंशिक परिवर्तनीय बना दिया। इसकी सफलता से आकर्शित होकर सरकार ने 1993–94 मे व्यापारिक मदों के लिए रूपये को पूर्ण परिरवर्तनीय बना दिया।

इनके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार के लिए यह निर्णय लिया गया कि घाटे वाली इकाइयो को गैर योजना ऋण नही दिए जाएगे एवं घाटे के सार्वजनिक उपक्रमों में अपनिवेश के लिए गठित आयोग की सिफारिशों के आधार पर सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर बेचकर अपनिवेश की नीति अपनाई गई। उपरोक्त आधार पर नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत उत्पादकता में वृद्धि, आधुनिक तकनीक का प्रयोग, उत्पादन क्षमता का पूर्ण विदोहन, राजकोशीय घाटे को कम करना, रोजगार गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का प्रभावशील ढंग से कियान्वयन, उदार ऋण नीति आदि प्राथमिकताए निर्धारित की गई।

आर्थिक सुधारों के मूल्यांकन पर एक दृश्टि– उपरोक्त विश्लेशण से स्पश्ट है कि 1991 के आर्थिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए गए। भारतीय अर्थव्यवस्था में इन सुधारों का 1991 से अब तक मिला जुला प्रभाव देखने को मिला है। ढांचागत सुधारों में पहले दो वर्शो में औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन में मंदी का दौर रहा। 1993–94 से इस क्षेत्र में फिर से उत्पादन बढने लगा। 2009–10 में औद्योगिक उत्पादन संवृद्धि दर 10.5 थी। वर्तमान समय में भी इस क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इसके अलावा भी 1991से विभिन्न क्षेत्रों में भी अर्थव्यवस्था में उतार चढाव आए है।

तालिका –2

भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार के बाद की स्थिति

प्रतिशत में

क्र	संकेतक	1991	2001	2011	2018
1	सकल घरेलू उत्पाद	5.9	8.00	8.3	7.2
2	प्रति व्यक्ति आय रू. में	26,915	39,547	63,462	1,14,998
3	विकास दर	6.24	6.78	8.9	7.2
4	मुद्रा स्फीति	10.3	5.5	9.4	3.6
5	बचत दर	21.6	24.8	34.6	30.5
6	निवेश दर	24.6	26.0	18.5	9.3
7	आयात वृद्धि	10.8	7.4	39.3	21.1
8	निर्यात वृद्धि	35.0	3.8	28.9	10.0

स्त्रोत– आर्थिक समीक्षा 2008–09, 2018–19

तालिका से स्पष्ट है कि आर्थिक सुधार के बाद

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-10, No.-I, Issues-11 YEAR- June -2019

सकल घरेलू उत्पाद एवं विकास दर में 1991 से 2018 तक कमी व वृद्धि हुई हैं, जबकि प्रति व्यक्ति आय में निरन्तर वृद्धि पायी गयी। अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति में गिरावट आयी। बचत एवं निवेश दर में उतार चढाव देखने को मिले है। आयात में 2011 में अधिक वृद्धि पर 2018 में कम हुआ। निर्यात 1991 मे वर्तमान की तुलना में अधिक थे अर्थात् निर्यातों में कमी हुई है।

नई आर्थिक नीति की कमियां– ढांचागत सुधारों की मिली जुली उपलब्धियों के बावजूद आर्थिक सुधारों की काफी आलोचना हुई। Economic and Political weekly research foundation ने लिखा है "नई आर्थिक नीति अपनी संकल्पना में .....विशय वस्तु में दृश्टिकोण एवं युक्ति और कुछ अन्य बातों में दोशपूर्ण है।" अतः इन कमियों को निम्न बिन्दुओं में संजोया जा सकता है–

समश्टि आर्थिक स्थिरीकरण और आधारभूत सुधारों के लक्ष्य उद्योग में प्रतियोगी वातावरण, जिसमें उद्यम संबंधी निर्णय केवल बाजार शक्तियों पर आधारित हो, तैयार करने पर है। जबकि सरकार की औद्योगिक संवृद्धि दर में वृद्धि के लिए कोई सकारात्मक भूमिका नही रही।

राजकोशीय, राजस्व तथा बजटीय घाटों में भारी कमी के लिए पहले गैर विकास व्यय में कटौती और कर आधार में विस्तार करना आवश्यक था किंतु सरकार ने वित्तीय सुधार कार्यक्रम कर दर में कमी और पूंजीगत व्यय में कटौती के द्वारा प्रारम्भ किया। इसके अलावा सरकार ने बिना निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश की मात्रा बढाए सरकारी पूंजीगत व्यय में कटौती कर दी।

सुधारों को लागू करने में अनावश्यक जल्दबाजी का कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था का शीघ्रातिशीघ्र अंग बनाने का विवादास्पद लक्ष्य था। इन सुधारों ने भारतीय उद्योग को न तो संभलने का मौका दिया और न ही संतुलन की उपयुक्त व्यवस्था की।

आर्थिक सुधारों से भारत में संवृद्धि की दर और प्रति व्यक्ति आय बढी। लेकिन इससे न तो गरीबी में कमी आई। न ही आय की असमानता में कमी आई। धनी परिवारो का पारिवारिक व्यय में हिस्सा 1994 में 39.3 प्रतिशत से बढकर 2004–05 में 45.3 प्रतिशत तक जा पहुँचा। इसी दौरान सबसे निर्धन परिवारो का पारिवारिक व्यय में हिस्सा 9.2 प्रतिशत से कम होकर 8.1 प्रतिशत ही रह गया।

आर्थिक नीति में मानव विकास के लक्ष्य ढाचागत समायोजनो की युक्ति के अभिन्न अंग होने चाहिए लेकिन दुर्भाग्यवश भारत में ऐसा कुछ भी नही किया गया।

आधारिक संरचना क्षेत्रक में भी अपेक्षित सफलता प्राप्त न हो सकी, निजी क्षेत्र केवल बड़ी परियोजनाओं में या लाभ के क्षेत्र में ही हाथ डालना चाहते हैं।

अतः आर्थिक सुधार कार्यक्रमों की उपलब्धियां अत्यधिक आकर्शक नही रही है यद्यपि कुछ क्षेत्रों की उपलब्धियां उत्साहवर्धक रही किंतु इनसे आय की असमानता बढी है। आवश्यकता है कि आर्थिक सुधार न्याय, समता, आत्मनिर्भरता एवं संवृद्धि के मूलभूत स्तम्भों पर केन्द्रित हो इसके लिए निम्न रणनीति अपनाई जा सकती है–

आर्थिक सुधारों को इस प्रकार लागू किया जाए, जिससे रोजगार व क्रयशक्ति में वृद्धि हो और निर्धन को इसका लाभ मिले।

सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करते हुए कृशि का व्यवसायीकरण किया जाए।

आधारिक संरचना क्षेत्रक में बड़े पैमाने पर निवेश किया जाए। जहा निजी क्षेत्र आगे न आए वहां सार्वजनिक निवेश को बढाया जाए।

वाणिज्यिक बैंको तथा वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिए जाए कि वे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कृषि एवं ग्रामीण विकास, गैर सरकारी संगठन से संबंधित विकास, पुश्प खेती, बागवानी, ग्रीन हाउस खेती, भवन निर्माण आदि योजनाओं पर प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराए।

निष्कर्ष– नई आर्थिक नीति में उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों के माध्यम से वैश्वीकरण के भारत सहित अनेक देशों पर सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। निजीकरण को लोकउपक्रमों की कमियों को दूर करने वाला एक प्रभावी उपकरण माना गया है। नई आर्थिक नीति में अपनाए गए सुधारवादी उपायों की परिणति आज उदारीकरण एवं निजीकरण की सीमा से निकलकर अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के रूप में परिलक्षित हो रही है।

आर्थिक सुधारों के परिणामरूवरूप सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर अन्य देशो की तुलना में अधिक है लेकिन रोजगार सृजन व गरीबी उन्मूलन में संतोशजनक नही है। अतः इन सुधारों को इस प्रकार लागू करना होगा जिससे लघु कुटीर उद्योग पर विदेशी पूंजी का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, रोजगार वृद्धि हो, निर्धनता व आय वितरण की असमानता को कम किया जा सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल ए. एन., भारतीय अर्थव्यवस्था (विकास एवं आयोजन), न्यू एज इन्टरनेशनल एण्ड लिमि. पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2010
2. पद्मावती, ग्रमीण निर्धनता : निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का मूल्यांकन, तिवारी पब्लिकेशन, 1991

3. रुद्रदत्त, सुन्दरम के. पी . एम., भारतीय अर्थव्यवस्था, एसचंद्र एण्ड कंपनी लिमि., नई दिल्ली, 2011
4. मिश्र एस. के., पुरी के., ''भारतीय अर्थव्यवस्था'', हिमालया पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई, 2019
5. आर्थिक समीक्षा 2008–09, 2018–19
6. परीक्षा वाणी, भारतीय अर्थव्यवस्था, इलाहाबाद।
7. भारतीय अर्थव्यवस्था, धनकर प्रकाशन, कानपुर।

*****